अन्य क्वाड

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

20 अक्टूबर, 2021

भारत को ईरान के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए भले ही वह अमेरिका-इजरायल-यूएई ब्लॉक (समान राजनीतिक हित वाले देशों का गुट) के साथ साझेदारी चाहता है।

भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में बदलाव की एक मजबूत अभिव्यक्ति है। अगर एक साल पहले देखा जाए तो इजरायल और यूएई के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध तक भी नहीं थे, लेकिन अब उनका बढ़ता आर्थिक और रणनीतिक सहयोग भारत सहित अन्य शक्तियों के लिए अवसर खोल रहा है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इजरायल में अपने इजरायली समकक्ष यायर लैपिड से मुलाकात के बाद क्वाड सम्मेलन में शामिल हुए, जहां वे एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। चार देशों की यह बैठक पश्चिम एशिया क्षेत्रीय विदेश नीति की दिशा में एक रणनीति अपनाने की भारत की इच्छा की ओर भी इशारा करती है।

जो अभी तक भारत के इस क्षेत्र को लेकर मौजूद द्विपक्षीयवाद की नीति से आगे जाती है। इन वर्षों में, भारत ने समूह के सभी देशों के साथ जीवंत द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं। यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड का सदस्य है, जिसकी पूर्वी एशिया पर समान चिंताएं और साझा हित हैं। इजराइल भारत के शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ लाखों भारतीय कामगार भी कार्य करते हैं। इस खाड़ी देश ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने में रुचि दिखाई है।

अतीत में, भारत की पश्चिम एशिया नीति के तीन स्तंभ थे- सुन्नी खाड़ी राजतंत्र (मुख्यत: सऊदी अरब तथा यूएई), इजराइल और ईरान।

अब जबकि सुन्नी राजतंत्रों और इजराइल के बीच की खाई को कम किया जा रहा है, विशेष रूप से अब्राहम समझौते (एकॉर्ड) के बाद, ट्रम्प प्रशासन के संरक्षण में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच सामान्यीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, भारत को क्षेत्रीय दृष्टिकोण के लिए कम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारतीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने संकेत दिया है कि चारों देशों के बीच और बैठकें होंगी। हालांकि इस तरह के समूह के रणनीतिक महत्व के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यह अपने जुड़ाव को गहरा कर सकता है - व्यापार, ऊर्जा संबंध, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना।

लेकिन भारत को इस क्षेत्र की चुनौतियों से भी सावधान रहना चाहिए। अमेरिका स्पष्ट रूप से चीन के उदय (Growth) से निपटने के लिए पूर्वी एशिया को अब अपनी धुरी के हिस्से के रूप में बना रहा है तथा इस क्षेत्र में अपनी पहुँच (पदचिह्न)को कम करने की कोशिश कर रहा है। जिससे वह पश्चिम एशिया के पारंपरिक समीकरणों को फिर से तैयार कर रहा है।

भारत को सावधान रहना चाहिए कि वह पश्चिम एशिया के कई संघर्षों में न फंस जाए जो बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के बीच तेज हो सकते हैं। जबकि अब्राहम समझौते (एकॉर्ड) ने भारत के लिए इजरायल और अमीरात के साथ आम जमीन खोजना आसान बना दिया, इस उभरते हुए ब्लॉक और ईरान के बीच विरोधाभास हमेशा की तरह तीव्र बना हुआ है।

भारत, जो खुद को भारत-प्रशांत में अमेरिका के साथ गठबंधन करता हुआ देखता है, अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद महाद्वीपीय एशिया में गहरी असुरक्षा का सामना कर रहा है और इसे अमेरिका के बाद के अफगानिस्तान से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा।

इसलिए नई दिल्ली के सामने चुनौती ईरान के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने की है, भले ही वह यू.एस.-इज. राइल-यूएई ब्लॉक के साथ एक मजबूत क्षेत्रीय साझेदारी का निर्माण करना चाहता है।

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

अब्राहम एकॉर्ड क्या है?

- 'अब्राहम एकॉर्ड (Abraham Accord) इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है।
- गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना के लिये एक नींव का काम करेगा, हालाँकि इस समझौते में इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई है।
- ध्यातव्य है कि 13 अगस्त, 2020 को इजराइल-यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन-इजराइल समझौते की घोषणा की गई थी।
- इस समझौते के अनुसार, यूएई और बहरीन द्वारा इजराइल में अपने दूतावास स्थापित करने के साथ पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- साथ ही इस समझौते के तहत इजराइल ने वेस्ट बैंक की बस्तियों को इजराइल में जोड़ने की अपनी योजना को 'स्थगित' कर दिया है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. अब्राहम समझौता निम्नलिखित में से किन के मध्य किया गया था?

(a) अमेरिका-इजरायल

(b) सऊदी अरब-इजरायल

(c) यूएई-इजरायल

(d) ईरान-इजरायल

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. The Abrahamic Pact was made between which of the following?

(a) America-Israel

(b) Saudi Arabia-Israel

(c) UAE-Israel

(d) Iran-Israel

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. पश्चिमी एशिया में इजरायल और कुछ अरब देशों के मध्य सम्बन्धों के सामान्यीकरण के संदर्भ में भारत के लिए क्या रणनीतिक लाभ के मौके उपजे हैं? भारत को इस क्षेत्र के संदर्भ में क्या नीति अपनानी चाहिए?

(250 शब्द)

Q. What strategic advantage opportunities have arisen for India in the context of normalization of relations between Israel and some Arab countries in West Asia? What policy should India adopt with regard to this region?

(250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।